

रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355 / 79

डाक पंजीकरण संख्या :- के पी सिटी- 67 / 2021-23

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में  
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

वर्ष -43 • अंक -6 एवं 7 • कानपुर 1 से 15 अप्रैल 2021 • प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट [www.dhr.gov.in](http://www.dhr.gov.in) लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु [log in करें www.behm.org.in](http://log in करें www.behm.org.in)

पत्र व्यवहार हेतु पता :-  
सम्पादक  
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट  
127 / 204 'एस' जूही,  
कानपुर-208014

## इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को

# अब नहीं जाना होगा C.M.O कार्यालय

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन के सम्बन्ध में जहाँ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 प्रयासरत रहा वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाई) ने भी अपनी महती भूमिका निभायी जिसके परिणाम स्वरूप शासन को प्रभावी कदम उठाना पड़ा इसकी परिणित तब हुई जब उत्तर प्रदेश शासन के आयुष अनुभाग-1 ने कार्यालय ज्ञाप जारी किया, आयुष अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप से यह स्पष्ट हो चुका है कि जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी अब केवल एलोपैथी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का ही पंजीयन करेंगे, आयुष अनुभाग-1 के इस आदेश से उन्हें भी अधिकार प्राप्त हो गया जिनकी जनपदीय पंजीयन में कोई भूमिका नहीं थी अर्थात् आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी के जनपदीय पंजीयन का अधिकार इनके जिला/क्षेत्रीय अधिकारियों को बिना किसी प्रयास से प्राप्त हो गया है, इस प्रयास में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है इसके साथ ही प्रदेश में अवमानवाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 को जहाँ विस्तार मिला है वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधिकार सीमित भी हो गये हैं, आयुष अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71-आयुष-1-2016-डब्ल्यू-283/2014 दिनांक 3 अगस्त, 2016 में वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करते हुए जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी को मात्र एलोपैथी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का ही पंजीयन का अधिकार दिया गया है, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी को आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों तथा जिला होम्योपैथिक अधिकारी को होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन का अधिकार प्रदान किया गया है, आयुष अनुभाग-1 के उपरोक्त आदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 के

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/ पाँच-6-10-23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को इलेक्ट्रो

चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने प्रवक्ताओं का आवाहन किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों / चिकित्सालयों के पंजीयन में यदि कोई असहजता

पहुँचने में बोर्ड ने अथक प्रयास किये हैं वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने अपना भरपूर प्रयास करते हुए

- ✓ इहमाई की मेहनत रंगलाई
- ✓ शासन को करना पड़ा शासनादेश
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों में आया नया जोश
- ✓ अब पूर्ण मनोयोग से निर्भीक होकर करेंगे अपनी पद्धति में प्रैक्टिस
- ✓ C.M.O. के स्थान पर जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकारी करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जनपदीय पंजीकरण
- ✓ किसी भी असहजता की मध्यस्थता करेंगे क्षेत्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकारी
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक सुनिश्चित करें आचार संहिता का पालन

होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के जनपदीय पंजीयन का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के जनपदीय पंजीयन अद्यतन व्यवस्थानुसार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है इस सम्बन्ध में बोर्ड के प्रवक्ताओं की एक आवश्यक बैठक दिनांक 31 मार्च, 2021 को बोर्ड के लखनऊ कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें प्रवक्ताओं को जनपदीय पंजीयन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गयी तथा उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से अतिरिक्त अन्य विद्याओं के चिकित्सकों के साथ-साथ आमजन को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता एवं जनपदीय पंजीयन की उपयोगिता के सम्बन्ध बतायें। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के

होती है तो उसका क्षेत्रीय अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से शमन कराने का प्रयास करें यदि इसमें कोई समस्या हो तो सीधे वह मामला बोर्ड को सन्दर्भित करें, डा0 इदरीसी ने आगे कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस स्थिति तक

लगातार भारत सरकार से सम्पर्क बनाये रखा है तथा देश में संचालित अनेक शीर्ष संस्थाओं से इस सम्बन्ध में लगातार विचार विमर्श जारी रखे हुए है। डा0 इदरीसी ने प्रवक्ताओं को सम्बोधित करते

हुये कहा कि आप चिकित्सकों से शासन के आयुष अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में है उसका व्यापक स्तर पर प्रचार एवं प्रसार करें तथा इनकी अधिकारिता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में चिकित्सकों को अवगत करायें तथा बोर्ड द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करने हेतु प्रेरित करें ताकि आयुष अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के मूल आदेश जिसके अनुपालन में यह कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। ज्ञातव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन के सम्बन्ध में शासन स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन हेतु कार्यवाही चल रही थी इसी मध्य प्रदेश में चिकित्सकीय अभिलेख उपलब्ध कराने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लाम्बित था जिसको निस्तारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह इस मामले का निस्तारण करते हुए उचित आदेश जारी करे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आयुष अनुभाग-1 ने सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप जारी किया।



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी लखनऊ कार्यालय में बोर्ड के प्रवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में वार्ता करते हुये साथ में हैं बोर्ड की ओ0एस0डी0 श्रीमती शाहिना इदरीसी



व्यवहारिक चिकित्सा पद्धति है

इलेक्ट्रो होम्योपैथी



इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगभग 150 वर्षों से भी अधिक समय से व्यवहार में लायी जा रही है, इससे अनेकों असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को अप्रत्याशित लाभ के प्रमाण भी मिलते हैं, इसी कारण यह चिकित्सा पद्धति निरन्तर आगे बढ़ते हुये अपने नये कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है, इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने में कोई भी किसी प्रकार की बाधा दूर-दूर तक नहीं है।

अब प्रश्न उठता है कि इतना सबकुछ होते हुये भी (जिसमें भारत सरकार द्वारा गठित प्क भी अपना सहयोग समय-समय पर देती रही है) लोग वस्तुस्थिति को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, प्रायः यह देखा गया है कि सरकार ने जब-जब कुछ मांगने का प्रयास किया तो प्रपोजलिसट कमेटी के सदस्यों ने कोई रुचि नहीं दिखायी **आखिर क्यों?** यह भी एक ज्वलन्त प्रश्न बनता है! आप माने या न माने परन्तु यह सत्य है कि कभी न कभी यह प्रश्न प्रपोजलकर्ताओं से किया जा सकता है तब उनके पास क्या उत्तर हो या यह तो समय ही बतायेगा।

जहाँ तक बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी की व्यावहारिकता की है तो पाठकों को बताते चलें कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 1998 के निर्देशानुसार भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि पहले से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां यथा आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी ही निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती हैं अतः अन्य गैर मान्यता प्राप्त (इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित) चिकित्सा पद्धतियां मापदण्ड पूर्ण नहीं करती हैं इसलिये इन्हें मान्यता नहीं प्रदान की जाती है, सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों में बैचलर व मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जा सकते हैं, सरकार ने विशेषज्ञ समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुये सभी राज्य सरकारों एवं समस्त केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किये कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई भी संस्था डिग्री / डिप्लोमा जारी न करें तथा इसके चिकित्सक अपने नाम के साथ डॉक्टर (Dr.) शब्द का प्रयोग न करें इस आशय के आदेश भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को जारी किया गया था।

25 नवम्बर, 2003 के आदेश की व्याख्या देश की अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं ने नकारात्मक रूप में की जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में वर्ष 2004 से 2010 तक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने दिनांक 05 मई, 2010 को एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास एवं अनुसंधान को निषेध नहीं किया गया है, इसमें आगे यह भी कहा गया है कि पूर्व की भाँति चिकित्सा एवं शिक्षा का कार्य करते रहेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह कार्य आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार किया जा रहा हो।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की व्यवहारिकता को संज्ञान में लेते हुये ही भारत सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दावेदारों से प्रस्ताव आमंत्रित किये, सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुपालन में लगभग 100 दावेदारों ने अपने-अपने दावे प्रस्तुत किये जिसमें से कुछ दावे तो प्रारम्भिक (Primary Stage) अवस्था में ही निरस्त कर दिये गये, कुछ चरणों के परीक्षण के बाद 29 दावेदारों के आवेदन स्वीकार कर लिये गये।

निरन्तर परीक्षण के बाद अन्तर विभागीय समिति ने सभी दावेदारों को सूचित किया कि अधिकांश दावे एक दूसरे की नकल (Copy-Paste) दिखयी दे रहे हैं अतः सभी दावेदार संयुक्त रूप से एक ही प्रपोजल प्रस्तुत करें, सभी दावेदारों के दावों में जो भी उपयोगी सामग्री हो उसे सम्मिलित करते हुये सभी दावेदारों के नाम दिये जा सकते हैं जिससे सभी का हित बना रहे।

अब्रज की बात तो यह है कि इस पर भी दावेदारों में आम सहमति नहीं बन पायी अन्त में निष्कर्ष यह निकला कि दावेदारों के दो समूह बन गये, अन्ततः **IDC** को इसपर टिप्पणी करने का अवसर मिल गया जबकि **IDC** ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की व्यवहारिकता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

Continued from last issue

20. Dr. K. Bakshi, Hyderabad, stated that there was science, not miracle, in the treatments on cancer, kidney and heart ailments, and he had compiled scientific data for 30 years, and if permitted by the Chairperson, he could submit the same, along with the information on the cost involved. Chairperson asked him and Dr. S.K. Golam Masud to submit the same by way of a proper document, on behalf of the joint federation.

21. Vaid Kuldip Raj Kohli, Director (AYUSH), representative of the Government of Maharashtra, stated that though many scientific evidences / data would be there later on, but, to begin with, they had to submit some such data in the beginning itself to go ahead in the matter. He suggested that they might be allowed some sufficient time - and one year might be good enough - to compile such data. Chairperson supported his suggestion as the committee wants to provide them ample chance in the matter, and did not want to close the chapter.

22. Being invited by the Chairperson, Dr. Rajni Kaul, Scientist G, ICMR, commented that the Standing Committee, constituted by the Ministry of Health and Family Welfare on 27.08.1999, had considered the electrohomeopathy system, based on the essential and desirable criteria laid down by the committee, and this Indian system was not recommended for recognition. And, after so many years today, this system was again unable to satisfy the information required in respect of laid-down criteria, which were further endorsed by IDC. The electrohomeopathy practitioners should submit the compiled data of, at least, last five years, showing clinical promise in specific indications.

23. Prof. (Dr.) Rajat Chattopadhyay, Principal, Calcutta Homoeopathic Medical College & Hospital, representing the Government of West Bengal, stated that he completely agreed with what the Chairperson and other experts had emphasized on. He stated he attended earlier meeting also on the issue, and the need for genuine scientific data was highlighted earlier also. Some papers were submitted that time also, but that was not sufficient. He observed that whatever literature had been submitted now, that did not look to have been taken from reputed scientific journals. He mentioned that huge clinical data and scientific evidence would be required, along with good and reputed publications on the subject.

24. Elaborating on valuable inputs from the West Bengal representative, the Chairperson advised Dr. Kuldip Tiwari to initiate the job of compiling a presentable data document as well as making of a good journal, and in this exercise, they should take along everybody in this field. Chairperson mentioned that in the case of acupuncture, contributions to journals were made by not only the acupuncturists but by the Allopaths also. He advised that they could take inputs and help from experts like Dr. Y.K. Gupta, Dr. Patwardhan, Allopaths, Ayush doctors also. He observed that things could not be achieved in such matters through legal recourse or political pressure. Good scientific and authentic publications, journals, data document were unavoidable. Dr. Kuldip Tiwari appreciated the ideas given by the members and pleaded for more time. The Chairperson asked him to prepare guidelines also so that they could present their case in a proper way.

25. Chairperson then called upon Dr. L. Swasthicharan, Addl. DDG, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, for his inputs. Thanking the Chairperson, Dr. Swasthicharan commented that though some progress had been made in the presentations made by different members of the organizations, compared to that on the last occasion, but there was a long way to go. He totally agreed to the valuable observations and suggestions made by the Chairperson and other experts, and commented that there was need to put the case together very strongly. He stated that had he been one of members, he would make a checklist of all the



suggestions given in the meeting, and then he would try to collect all the evidences, all the case-studies, all the information that are available with the practitioners and then organize all these things in a systematic way. Thereafter, he suggested, comparison with other systems, like Allopathy and Ayush, would be helpful to know precisely as to where this case stood. He added that comparison, particularly with the Ayush system, would be easier, for example, with Ayurveda, Homoeopathy, Siddha and other branches. He stated that so far some individualistic data was there, but it would not help, and the it must be a collective one. Only then, he concluded, some progress could be achieved.

26. Chairperson appreciated Dr. Swasthicharan, and observed that his inputs were very objective and open. He advised that the organizations must do it as there was no other way. He also observed that in view of the orders of the court to close systems not recognized, not much time was available for them to complete the exercise, and, may be, they would have to do it within this year. He reiterated that a good document should be there, and if there was some monogram on it, it could be used for further growth, and that there was no harm in making comparisons. He observed that though there was experience, there was expertise, but there was no collective effort for making a presentable and reliable scientific data-base and literature.

27. Summing up his inputs, Dr. Y.K. Gupta advised the organizations that they had a golden opportunity, with Dr. Katoch at the helm of the Inter-Departmental Committee, to achieve their cause with a do-or-die approach. Otherwise, may be, someday they might be asked to close down the system by court or other authority, but this committee was so much inclined to help them achieve their purpose. He stated that in spite of having experts, it was a fact that they did not have any good publications in any good and reputed scientific journal, and that might be due to absence of any proper system or facility and, also, but it might be difficult for them to put together overnight a realistic journal in a limited time, but there were certain things they could do now. First, they should do brain-storming session by bringing together all their experts in the country, then made a list of all the passed-out experts in the country with full details as to what they were doing, etc., assigned precise jobs to their people, organized 3 or 4 workshops to decide as to which documents to be made in, say three months for submission to this committee, as the document submitted for the current meeting was quite ineffective. The document should contain information about their strength area, investigations, the diseases that had been cured and how cured, etc. He observed that individual case-reports were regarded at the lowest level in the level of evidence. He said that there should be case series, followed with matter analysis, hypothesis, vision, plan for collaboration, etc. They should compile information about human resources available, how many books, laboratories and other infrastructure. He mentioned that they had some information/ data, but in a scattered manner. These should be properly compiled. Dr. Gupta's suggestions were appreciated by the Chairperson.

28. He then called upon other State representatives to offer their views in the matter. Dr. Brender Sharma, Deputy Director (Homoeopathy), Directorate of Ayush, Government of NCT of Delhi, stated that valuable suggestions had been given in the meeting, and there should be very valid and solid answer to these suggestions and they should focus on these, and there should be effort to find out scientific background in case they want to establish this system. Dr. Katoch thanked him for his inputs.

29. Thanking Dr. Brender Sharma for his inputs, Dr. Katoch, Chairperson, told Dr. Kuldip Tiwari that it was not that efforts were not made by them, but the fact was that those efforts were not up to the desired level. He observed that good inputs were provided in the earlier two meetings also, but today there had been very good and fruitful deliberations, with everybody coming up with very open and frank suggestions, joint body representatives too having spoken with open mind. He mentioned that different participants had spoken in their different way, but a common suggestion of compiling and presenting the data

in a meaningful way, has come up in the meeting.

30. Thereafter, the Chairperson requested Shri Anand Kumar Sharma, Additional Director (Ayurveda), Government of Rajasthan, for his comments. Shri Anand Kumar Sharma commented that he was attending the meeting for the first time, and that there was very fruitful discussion today. He informed that the Rajasthan Assembly had passed the Bill for recognition of the system in the year 2018, and, thereafter, the government has constituted another committee for the purpose of execution of the matter. He stated that similar things were discussed in the meetings of that committee, and the points discussed in today's meeting would be useful for the next meeting of that

committee. After requisite data, evidence was made available, further progress would be made in the matter. Chairperson appreciated the will-power and the efforts of the State Government to establish a new system, and requested Shri Sharma that whenever some progress was made, that may also be shared with the Department of Health Research and they may be kept in the picture, as they are also involved in the similar process. Shri Sharma thanked the Chairperson.

31. At the end, Dr. Abdulrazzaque Abdulhameed Qureshi mentioned that unless and until some validity was there from the Government side, how they could go ahead in the matter. Chairperson told him that there was no question of any validity from the Government side at this stage, and that they themselves would have to promote their case. He stated that the 'minutes' of this meeting would go to him also, and this might help them in the matter.

### 32. Conclusions

Common views in the meeting were that the proposal submitted for recognition of Electrohomoeopathy as a system of medicine, lacked detailed and authentic scientific information and data, without which the Inter-Departmental Committee was unable to properly assess the viability of the system and progress further. It was noted that in spite of the claims that this system was being widely practiced in the country for almost a century now, however, necessary records / documents did not appear to had been developed and maintained in combined and standard manner, which were very essential and unavoidable for promotion and further development of any system of healthcare. In the meeting today, all the experts, including those from the four State Governments, had been unanimous in their views that there ought to be properly-compiled detailed clinical data to establish the efficacy/efficiency of electrohomoeopathy treatment, a common standard pharmacopeia for manufacture of medicines in the country and related activities, publications in reputed scientific national / international journals and or well analysed monographs of clinical data from different centres, etc. All these issues were deliberated in detail in the meeting, and all the proponents of the system were advised to prepare a check-list of the things to be done, as suggested by each of the experts in the meeting, and then to initiate and complete the exercise in a do-or-die manner. They were advised to work together, taking along all in the trade in the country, so that they could compile common solid and valid data/documents for submission to the Inter-Departmental Committee for its further review. They were also assured that the committee was positively inclined towards their cause as the ultimate benefit would go the public. While it was agreed that they would require months to complete the exercise, however, they were advised to complete the job as early as possible.

33. Dr. Katoch, Chairperson, IDC, then thanked everybody, including the organizations, for their participation and useful contributions. Dr. Kuldip Tiwari, on behalf of the organizations, thanked the Chairperson, the committee members and others for their useful advice.

The meeting concluded with a vote of thanks from Shri D.R. Meena, Deputy Secretary, DHR, to the Chair and all the participants.



**बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०**

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8- लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ-226001

प्रशा० कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर-208014

website- [www.behm.org.in](http://www.behm.org.in)Email: [registrarbehmup@gmail.com](mailto:registrarbehmup@gmail.com)**प्रवेश सूचना****F.M.E.H.** दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष**G.E.H.S.** चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष**P.G.E.H.** दो वर्ष – **G.E.H.S** अथवा चिकित्सा स्नातक**C.E.H.** एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष**A.C.E.H.** एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें  
अथवा [www.behm.org.in](http://www.behm.org.in) पर log in करें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की परीक्षायें 7 अप्रैल से प्रारम्भ होंगी यह जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने एक विज्ञप्ति में दी, परीक्षा कार्यक्रम निम्न प्रकार है।फ

**BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE, U.P.**8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail [registrarbehmup@gmail.com](mailto:registrarbehmup@gmail.com)**PROGRAMME FOR EXAMINATION March 2021**

Name of the course	7 <sup>th</sup> April, 2021 Wednesday		8 <sup>th</sup> April, 2021 Thursday		9 <sup>th</sup> April, 2021 Friday		10 <sup>th</sup> April, 2021 Friday
	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting	2nd. Meeting	1st. Meeting
M.B.E.H. 2nd. Professional	Pathology 1st.	Pathology 2nd.	Hygiene & Health	Med. Jurisprudence & Toxicology	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.
M.B.E.H. Final Professional	Midwifery & Gynaecology 1st.	Midwifery & Gynaecology 2nd.	Ophthalmology incl. E.N.T. 1st.	Ophthalmology incl. E.N.T. 2nd.	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.
G.E.H.S. 1st. Professional	Anatomy 1st.	Anatomy 2nd.	Physiology incl Bio-Chem. 1st.	Physiology incl Bio-Chem. 2nd.	Pharmacy	Philosophy	XX
G.E.H.S. 2nd. Professional	Pathology incl. Micro.-Bio. 1st.	Pathology incl. Micro.-Bio. 2nd.	Forensic Science & Toxicology	Materia Medica	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX
G.E.H.S. 3rd. Professional	Obstetrics & Gynaecology 1st.	Obstetrics & Gynaecology 2nd.	Ophthalmology incl. E.N.T. 1st.	Ophthalmology incl. E.N.T. 2nd.	Environmental Science	Materia Medica	XX
G.E.H.S. Final Professional	Materia Medica & Therapeutics	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	Surgery	Physical & Health Education	XX	XX
P.G.E.H. 1st. Professional	Pharmacy	Philosophy	Materia Medica 1st.	Materia Medica 2nd.	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX
P.G.E.H. Final Professional	Materia Medica 1st.	Materia Medica 2nd.	Practice of Medicine 1st.	Practice of Medicine 2nd.	XX	XX	XX
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy & Philosophy	XX	XX	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	XX	Hygiene & Health	XX	Environmental Science	XX	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Ophthalmology including E.N.T.	XX	Med. Jurisprudence & Toxicology	XX	Dietetics	XX	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	XX	Materia Medica	XX	Practice of Medicine	XX	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy-Philosophy & Materia Medica	XX	Pathology-Hygiene & Health- Med. Jurisprudence & Toxicology	XX	Midwifery-Gynaecology-Ophthalmology incl. E.N.T. & Practice of Med.

Timing < 1st. Meeting : 8:00 A.M. to 11:00 A.M.  
2nd. Meeting : 2:00 P.M. to 5:00 P.M.Atiq Ahmad  
Examination Incharge